



प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07/02/2024

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ के पत्र संख्या- इटप/प्रशा०/2023-24/363, दिनांक 08.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू०-6,51,48,000.00 (रूपया छः करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू०-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से अनुमन्य अग्रिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू०-6,51,48,000.00 (रूपया छः करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या- 9/2023/77-1-2022-02बजट-15/001-787 दिनांक 03.05.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू०-1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सम्प्रति धनराशि रू०-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) अवशेष है। अतएव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में उक्त अवशेष धनराशि रू०-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से धनराशि रू०-1,10,00,000.00 (रूपया एक करोड़ दस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा उसकी समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण किये जाने का दायित्व संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ का होगा।
3. धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध करायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001800 इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-227-X-2023-24, दिनांक 03.02.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)

अनुसचिव,

उ०प्र० शासन।

संख्या-5/2024/77-1002(002)/1/2022/001-27, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु०-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)

अनुसचिव,

उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।